मालगाड़ी की 24 कि.मी. प्रति घंटा है, जो ट्रैक्टर की गति के बराबर है, जबकि बजट में सुपरसोनिक गति के सपने दिखाए गए हैं। बजट घोषणाएं जन-मानस को सतही तौर पर प्रफुल्लित कर सकती हैं, परन्तु देश का स्वरूप बदलने में सक्षम नहीं है। 25 रुपए में मासिक पास देना प्रशंसनीय है, परन्तु गाड़ी में बैठने का स्थान उपलब्ध कराना उससे भी जरूरी है। दैनिक सवारी डिब्बों में यात्री भेड़-बकरियों की तरह भरे जाते हैं। सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। माल गाड़ी के डिब्बे केवल मोटे उत्पाद जैसे कोयला, सीमेंट, लोहा, खाद आदि ढोने के योग्य हैं। इसीलिए माल भाड़े का 45 प्रतिशत भाड़ा केवल कोयला ढुलाई से आता है। मालगाड़ियों के डिब्बों को अन्य उत्पादों की ढुलाई के अनुरूप बदलने एवं व्यापारियों की सुविधा के अनुसार सेवा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रेल ढांचे को इक्कसवीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाए बदले एवं आधुनिकीकरण करे। धन्यवाद।

**Demand to provide medical help to cure the people suffering from an unidentified disease in Kandhamal District of Orissa**

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, thirteen persons including eleven children died in Daring Badi of Kandhamal district in Orissa suffering from an unidentified disease. About hundred more are affected. The State Health Department is unable to control the disease and is saying that it could be Malaria or some sort of fever. It is spreading like wild fire from one village to another. This part is also affected by Naxal violence. Neither the affected people are willing to go to the Daring Badi Health centre nor the mobile health centre is reaching the affected persons. The situation is very alarming.

I urge upon the Government to send a team of doctors with sufficient medicine and CRPF police protection to help the affected persons in Daring Badi in Kandhamal district of Orissa.

**Demand to withhold disinvestment in Coal India Limited**

**श्री आर.सी. सिंह** (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ इस माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि Coal India Limited Company और देशवासियों के विरोध के बावजूद कोयला मंत्री Coal India Limited में विनिवेश करने पर आमादा हैं। कल और परसों मीडिया में भी यह खबर आई है कि CIL में 10 प्रतिशत शेयर का विनिवेश करने के लिए कोयला मंत्रालय प्रधान मंत्री से शीघ्र मंजूरी लेगा। मंत्री जी का कहना है कि कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस संबंध में अपनी संस्तुति दी है। वास्तविक सच्चाई यह है कि CIL के बोर्ड पर ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह कम्पनी, उसके कर्मचारी और देश हित में नहीं है। हम CIL में किसी भी तरह के विनिवेश का विरोध करते हैं। CIL एक नवरत्न कम्पनी है और पिछले साल इसने 8700 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।

सर, जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह के पॉलिसी डिसीज़न के बारे में सबसे पहले संसद को सूचित करे, लेकिन संसद की अवहेलना करके कोयला मंत्रालय ने यह प्रस्ताव बनाया है और शीघ्र ही यह उसे वित्त मंत्रालय की अनुमति के लिए भेज रहा है।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और अपील करता हूं कि वह CIL में विनिवेश न करे। यह न केवल इस कम्पनी के हितों के विरुद्ध है, बल्कि देश और देशवासियों के हित में भी नहीं है।

**श्री रुद्रनारायण पाणि** (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

**Demand to withhold disinvestment in NALCO**

**श्री रुद्रनारायण पाणि** (उड़ीसा) : महोदय, नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी (नाल्को) न केवल उड़ीसा, बल्कि समूचे देश का गौरव है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मुनाफा करने वाला एक उपक्रम है। अगर इसे ढंग से चलाया जाएगा, तो यह और अधिक मुनाफा दे सकता है। इसमें पूंजी विनिवेश किए जाने के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। इस कम्पनी को गतवर्ष नवरत्न घोषित किया गया है, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस कम्पनी के CMD (चेयरमैन कम मैनेजिग डायरेक्टर) के पद पर अभी भी स्थाई रूप से कोई व्यक्ति नही है। अभी भी कई निदेशक के पद रिक्त है। ये सब पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए। महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा के कोरापुट स्थित माइन्स एंड रिफाइनरी संयंत्र में गत अप्रैल में चुनाव के दौरान नक्सली हमले हुए। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को कहा जाए, कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक-ठाक करे। महोदय, अभी नाल्को का अंगुल स्थित CPP (कैपिटल पावर प्लांट) कोयले के गंभीर संकट पर गुजर रहा है। कोल इंडिया के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के ताल्चर फील्ड्स में पर्याप्त कोयला है। वहां पर पता नहीं चलता है कि इसमें हर साल कोयले का संकट क्यों दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इस सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसानग्रस्त करने हेतु कहीं न कहीं साजिश की जा रही है, ताकि धीरे-धीरे इससे पूंजी विनिवेश कर लिया जाएगा एवं बाद में इसे निजी क्षेत्र वाले खरीद लेंगे। अतः सरकार से मेरी यह मांग है कि वह इसके प्रति सतर्क रहे और नाल्को हमेशा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बना रहे। ऊपर से इसके दोनों प्लांट साइट अर्थात् अंगुल और कोरापुट के दामनजोड़ी के पास एल्युमिनियम पार्क बनाया जाए और एनसिलियेरीज़ उद्योग हेतु अवसर बनाया जाए। जल्द.ी से जल्दी इसके विस्थापित की समस्या को हल कर दिया जाए। कम्पनी के अंदर और पैरिफेरी में रोज़गार के जो भी अवसर हैं, सब में लेस अफेक्टेड पीपल्स, यानी LAPs को भी मौका दिया जाए। कांट्रेक्टरों के नीचे जो भी हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, उन्हें एल्युमीनियम सेड्यूल के नाम से पैकेज दिया जाए। मेरी कुल मिलाकर यह मांग है कि नाल्को के सार्वजनिक क्षेत्र स्वरूप को कायम रखने हेतु भरपूर प्रयास किया जाए, न कि उससे पूंजी विनिवेश किया जाए।

**श्री भागीरथी माझी** (उड़ीसा) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

**Request for financial assistance to implement the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Andhra Pradesh**

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government of India has introduced the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana with an aim to provide access to electricity to all households in the country in five years, that is, by 2010. Andhra Pradesh is front-runner. The outlay of RGGVY is Rs.781.76 crores for four APDISCOMs for electrification of 14,182 unelectrified habitations and 37,99,213 rural households including 24,99,213 BPL rural households in 22 districts.

Out of above, REC has accorded scheme sanctions for 17 districts for an amount of Rs.648.29 crores during the month of October, 2005. Schemes for balance five districts, that is, East Godavari, Medak, Ranga Reddy, Warangal and Karimnagar for an amount of Rs.133.62 crores are accepted in principle by REC but sanction is awaited. DISCOMSs have already spent an amount of Rs.49.51